

प्रारंभिक परीक्षा

GM फसल पर विशेषज्ञ पैनल हितों के टकराव की घोषणा करेंगे

संदर्भ

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के लिए विशेषज्ञों के चयन संबंधी नियमों में संशोधन किया है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) के बारे में -

- GEAC पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए "आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड (संशोधित) जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग/आयात के नियम (नियम, 1989)" के तहत गठित एक वैधानिक समिति है।
- नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
- कार्य:
 - प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड (GE) जीवों और उत्पादों को जारी करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार।
 - यह आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) जीवों और फसलों के उपयोग, आयात और निर्यात पर नजर रखता है।
 - GM फसलों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए GEAC की मंजूरी अनिवार्य है।
- संघटन:
 - इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव करते हैं तथा सह-अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के प्रतिनिधि करते हैं।
 - सदस्य: 24
 - प्रस्तावों पर चर्चा के लिए GEAC की हर महीने बैठक होती है।

GEAC विशेषज्ञ चयन नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

- हितों के टकराव का खुलासा
 - विशेषज्ञ सदस्यों को किसी भी संभावित हित टकराव का खुलासा करना होगा जो उनके निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है।
 - निर्णयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
 - जिन विषयों पर चर्चा की जा रही है उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सदस्यों को बैठक से पहले इसकी घोषणा करनी होगी।
- चर्चा से अलग होना
 - जब तक समिति द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया जाए, मतभेद वाले सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रासंगिक चर्चाओं से स्वयं को अलग रखें।
- अनिवार्य व्यावसायिक प्रकटीकरण
 - चयनित सदस्यों को पिछले दशक की अपनी व्यावसायिक संबद्धता का विवरण देते हुए एक फॉर्म जमा करना होगा।

UPSC PYQ

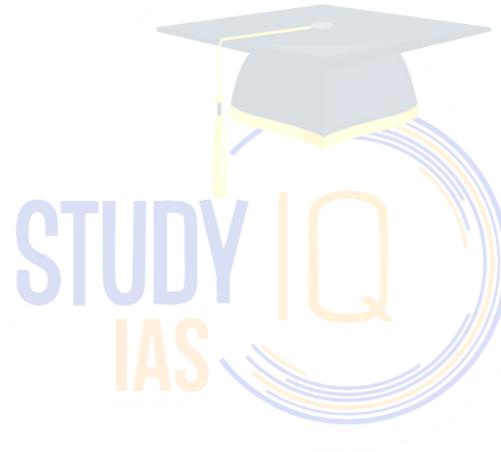
प्रश्न: जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके तहत किया गया है? (2015)

- (a) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- (b) वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
- (c) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (d) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

उत्तर: (c)

स्रोत:

- [द हिंदू - GM फसल पर विशेषज्ञ पैनल हितों के टकराव की घोषणा करेंगे](#)



भारतीय शोधकर्ताओं ने लक्षित कैंसर उपचार के लिए इंजेक्टैबल हाइड्रोजेल विकसित किया है

संदर्भ

बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के सहयोग से आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक इंजेक्टैबल हाइड्रोजेल विकसित किया है।

इंजेक्टैबल हाइड्रोजेल की मुख्य विशेषताएं -

- **अभिनव डिजाइन**
 - यह अति लघु पेप्टाइड्स से बना है, जो जैवनिम्नीकरणीय और जैवसंगत हैं।
 - हाइड्रोजेल इंजेक्शन स्थल पर स्थिर रहता है, जिससे स्थानीय उपचार सुनिश्चित होता है।
 - यह ग्लूटाथियोन (GSH) के बढ़े हुए स्तर की प्रतिक्रिया में सक्रिय होता है, यह एक अणु है जो ट्यूमर कोशिकाओं में उच्च सांद्रता में पाया जाता है।
- **सटीक दवा वितरण(Precision Drug Delivery)**
 - यह कैंसर रोधी दवाओं को नियंत्रित तरीके से जारी करता है, तथा स्वस्थ कोशिकाओं को छोड़ते हुए कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करता है।
 - पारंपरिक कीमोथेरेपी से जुड़े प्रणालीगत दुष्प्रभावों को न्यूनतम करता है।

हाइड्रोजेल्स के बारे में -

- **हाइड्रोजेल त्रि-आयामी, हाइड्रोफिलिक पॉलिमर नेटवर्क हैं जो अपनी क्रॉस-लिंक्ड प्रकृति के कारण संरचना को बनाए रखते हुए बड़ी मात्रा में पानी बनाए रख सकते हैं।**
- इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी होने के कारण ये प्राकृतिक ऊतकों के समान मुलायम और लचीले होते हैं।
- **संरचना:** हाइड्रोजेल प्राकृतिक या सिंथेटिक पॉलिमर से बनाये जा सकते हैं, जैसे कोलेजन, जिलेटिन, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल (पीईजी), सेल्यूलोज, स्टार्च, चिटिन और चिटोसिन।
- **अनुप्रयोग:**
 - **ऊतक इंजीनियरिंग(Tissue engineering):** हाइड्रोजेल का उपयोग ऊतक इंजीनियरिंग के लिए ढांचे के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संरचना कई ऊतकों के बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स के समान होती है।
 - **घाव भरना:** हाइड्रोजेल एक सामान्य घाव देखभाल समाधान है क्योंकि वे नरम, नमीयुक्त होते हैं और पानी को शीघ्रता से अवशोषित कर लेते हैं तथा उसे बनाए रखते हैं।
 - **दवा वितरण:** हाइड्रोजेल में दवा भरी जा सकती है तथा उसे त्वचा के नीचे, मुंह से या मांसपेशियों में नियंत्रित किया जा सकता है।
 - **पर्यावरणीय सफाई:** इनका उपयोग प्रदूषकों को पकड़ने और हटाने के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से पानी में।
 - **कृषि:** मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में।
 - **इनका उपयोग कॉन्टैक्ट लेंस और डायग्नोस्टिक उपकरणों में भी किया जाता है।**

UPSC PYQ

प्रश्न: निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजेल का उपयोग किया जाता है? (2024)

1. रोगियों में नियंत्रित दवा वितरण
2. मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम
3. औद्योगिक स्नेहक की तैयारी

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत:

- [द हिंदू - भारतीय शोधकर्ताओं ने लक्षित कैंसर उपचार के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया](#)



मोटापा गैर-संचारी रोगों की महामारी का केंद्र है

संदर्भ

मोटापा और अधिक वजन के कारण दुनिया भर में हर साल 3.4 मिलियन से अधिक मौतें हो रही हैं।

मोटापे के बारे में -

- मोटापा एक दीर्घकालिक बीमारी है जो तब होती है जब शरीर अतिरिक्त कैलोरी को वसा के रूप में संग्रहीत करता है।
- यह उपभोग की गई कैलोरी और व्यय की गई कैलोरी के असंतुलन के कारण होता है (जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक वसा या उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थ खाता है और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करता है)।
- **अन्य कारक:** कुछ दवाएं, जैसे अवसादरोधी, स्टेरॉयड और मधुमेह की दवाएं, नींद की कमी, तनाव और आनुवंशिकी।
- 30 से अधिक का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) मोटापे का संकेत देता है।
- मोटापे के कारण होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याएं: स्ट्रोक, टाइप-2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, कुछ कैंसर आदि।
- मोटापे से निपटने के लिए सरकार के प्रयास:
 - **ईट राइट इंडिया:** भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का एक अभियान जो स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देता है। इस अभियान के तीन स्तंभ हैं:
 - सुरक्षित भोजन करना: सुरक्षित और स्वच्छ भोजन को बढ़ावा देना।
 - स्वस्थ भोजन करना: आहार विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना।
 - टिकाऊ भोजन खाना: जल संसाधनों के संरक्षण, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को खाने को बढ़ावा देना।
 - फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आदि।

मोटापे के आँकड़े

- **वैश्विक:**
 - 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे के साथ जी रहा है।
 - 890 मिलियन वयस्क और 160 मिलियन किशोर इससे प्रभावित हैं।
 - 5 वर्ष से कम उम्र के 37 मिलियन बच्चे अधिक वजन वाले हैं और 5-19 वर्ष की आयु के 390 मिलियन बच्चे अधिक वजन वाले हैं।
- **भारत:**
 - 13% मोटापा दर, अन्य मध्यम आय वाले देशों की तुलना में अधिक।
 - मोटापे के मामले में भारत विश्व स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है।
 - मोटापे से ग्रस्त बच्चों के मामले में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।

स्रोत:

- [द हिन्दू - मोटापा: गैर-संचारी रोगों की महामारी का मुख्य कारण](#)

क्या राजाजी बाघ 500 किलोमीटर पैदल चलकर जम्मू आया था?

संदर्भ

नवंबर 2022 में राजाजी टाइगर रिजर्व से निकला एक युवा नर बाघ बाद में हरियाणा के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने के बाद हिमाचल प्रदेश के रेणुका वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया। इसे हाल ही में जम्मू के राजौरी में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सेना के गश्ती दल ने देखा था।

राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में -

- यह उत्तराखंड के 3 जिलों (देहरादून, हरिद्वार, पौरी गढ़वाल) में फैला हुआ है।
- यह शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों और तलहटी में स्थित है।
- 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए राजाजी वन्यजीव अभयारण्य को मोतीचूर और चिल्ला वन्यजीव अभयारण्यों के साथ मिला दिया गया।
- नदियाँ: गंगा और उसकी सहायक नदी सोंग इस रिजर्व से होकर बहती हैं।
- इसमें एक हाथी गलियारा है (चिल्ला-मोतीचूर) जो राजाजी और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच हाथियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है।
- वनस्पति: अर्ध-सदाबहार से लेकर पर्णपाती तक विविध प्रकार के वनों से आच्छादित।
- जीव-जंतु: बाघ(Tiger), एशियाई हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू, धारीदार लकड़बग्घा, गोरल आदि। बड़ी संख्या में तितलियाँ और छोटे पक्षी भी देखे जाते हैं।



स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - राजाजी टाइगर की जम्मू तक 500 किमी पैदल यात्रा

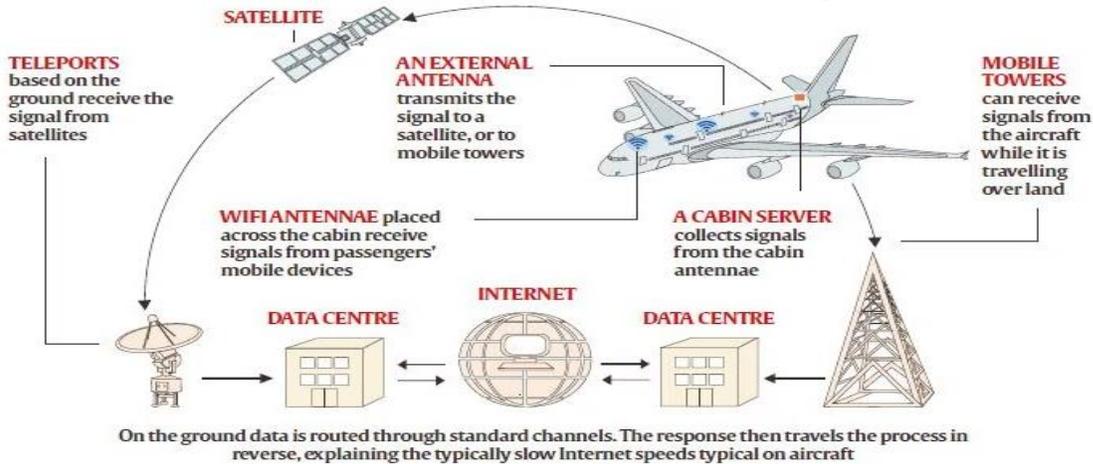
इन-फ्लाइट इंटरनेट कैसे काम करता है?

संदर्भ

एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह घरेलू उड़ानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन है।

इन-फ्लाइट वाई-फाई के पीछे की प्रौद्योगिकियाँ -

- **हवा से जमीन (ATG) प्रौद्योगिकी:**
 - जमीन पर सेलुलर टावरों का उपयोग करता है।
 - सिग्नल विमान के नीचे लगे एंटीना द्वारा प्राप्त किये जाते हैं।
 - **सीमाएँ:** बड़े जल निकायों या टावरों के बिना निर्जन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बाधित हो सकती है।
- **उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी:**
 - विमान के मुख्य भाग पर लगे एंटीना के माध्यम से जमीनी स्टेशनों और उपग्रहों के बीच सिग्नल प्रसारित करता है।
 - व्यापक कवरेज प्रदान करता है, विशेष रूप से सेलुलर टावरों के बिना दूरदराज के क्षेत्रों में उपयोगी है।
- **प्रक्रिया:**
 - यात्रियों के उपकरणों से आने वाले सिग्नल केबिन में लगे वाई-फाई एंटेना द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
 - ये सिग्नल ऑन-बोर्ड सर्वर पर भेजे जाते हैं।
 - सर्वर से सिग्नल या तो उपग्रहों (उपग्रह-आधारित कनेक्टिविटी के लिए) या ग्राउंड टावरों (एटीजी के लिए) को प्रेषित किए जाते हैं।
- **वाई-फाई सुविधा प्रदान करने वाले विमान:** एयरबस ए350, बोइंग 787-9 और एयरबस ए321neo।
- **चुनौतियाँ:**
 - वाई-फाई एंटीना लगाने में काफी लागत आती है। एयर इंडिया अपने पुराने विमानों को वाई-फाई हार्डवेयर से अपग्रेड करने के लिए 400 मिलियन डॉलर के रेट्रोफिट कार्यक्रम से गुजर रही है।
 - उड़ान के दौरान वाई-फाई, जमीन पर आधारित इंटरनेट की तुलना में धीमा होता है।



स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - विमान में इंटरनेट कैसे काम करता है, इस पर एक नजर](#)

शीतकालीन चार धाम सर्किट

संदर्भ

उत्तराखण्ड सरकार ने सर्दियों के ऑफ-सीजन महीनों के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीतकालीन चार धाम सर्किट का उद्घाटन किया है।

चार धाम के शीतकालीन स्थलों के बारे में -

- सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण मुख्य चार धाम मंदिर तक पहुंचना दुर्गम हो जाता है।
- मुख्य देवताओं को **निचली ऊंचाई वाले मंदिरों में ले जाया जाता है**, जिन्हें उनका शीतकालीन निवास स्थान घोषित किया जाता है:
 - **गंगोत्री धाम:** मुखबा (उत्तरकाशी)।
 - **यमुनोत्री धाम:** खरसाली (उत्तरकाशी)।
 - **केदारनाथ:** ओंकारेश्वर मंदिर (ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग)।
 - **बद्रीनाथ:** पांडुकेश्वर (चमोली)।
- **आर्थिक महत्व:** चार धाम तीर्थयात्रा उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो **पीक सीजन के दौरान प्रतिदिन 200 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करती है**। सर्दियों में चार धाम यात्रा का उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करके ऑफ-सीजन में आर्थिक लाभ को बढ़ाना है।
- **पर्यावरण एवं प्रबंधन संबंधी चिंताएं:**
 - **भीड़भाड़ और बुनियादी ढांचे पर दबाव:** यात्रियों की बढ़ती संख्या स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है।
 - **वन्य जीवन पर प्रभाव:** हिम तेंदुए, पहाड़ी भेड़ जैसे जानवर सर्दियों के दौरान भोजन और पानी की तलाश में निचले इलाकों में चले जाते हैं, शीतकालीन पर्यटन इन शर्मिली प्रजातियों को परेशान कर सकता है।
 - **सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम:** पर्वतीय क्षेत्रों में कठोर मौसम और चुनौतीपूर्ण भूभाग तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा, संरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं।



स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - शीतकालीन चार धाम क्या है?](#)

पल्लास बिल्ली (Palla's Cat)

संदर्भ

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुए के सर्वेक्षण के दौरान पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला।

पल्लास बिल्ली के बारे में -

- इसका नाम पीटर साइमन पल्लास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1776 में पहली बार इसका वर्णन किया था।
- वितरण: यह यहाँ की मूल प्रजाति है मध्य एशिया, जिसका विस्तार पश्चिमी ईरान, मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान तक है।
- विशेषताएँ:
 - इसका फर घना, चांदी जैसा भूरा होता है तथा चेहरा चपटा तथा कान गोल होते हैं।
 - यह एकान्तवासी और छिपने वाला प्राणी है, तथा मुख्यतः रात्रि में सक्रिय रहती है।
 - निवास स्थान: चट्टानी मैदानों और ठंडे रेगिस्तानों में 5,000 मीटर तक की ऊँचाई पर रहती है।
 - यह छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और कीड़ों को खाती है।
- संरक्षण की स्थिति:
 - आईयूसीएन: कम चिंताग्रस्त
 - सीआईटीईएस: परिशिष्ट II



स्रोत:

- [द हिन्दू - पल्लास बिल्ली पाठ्यपुस्तक में जगह पाती है](#)

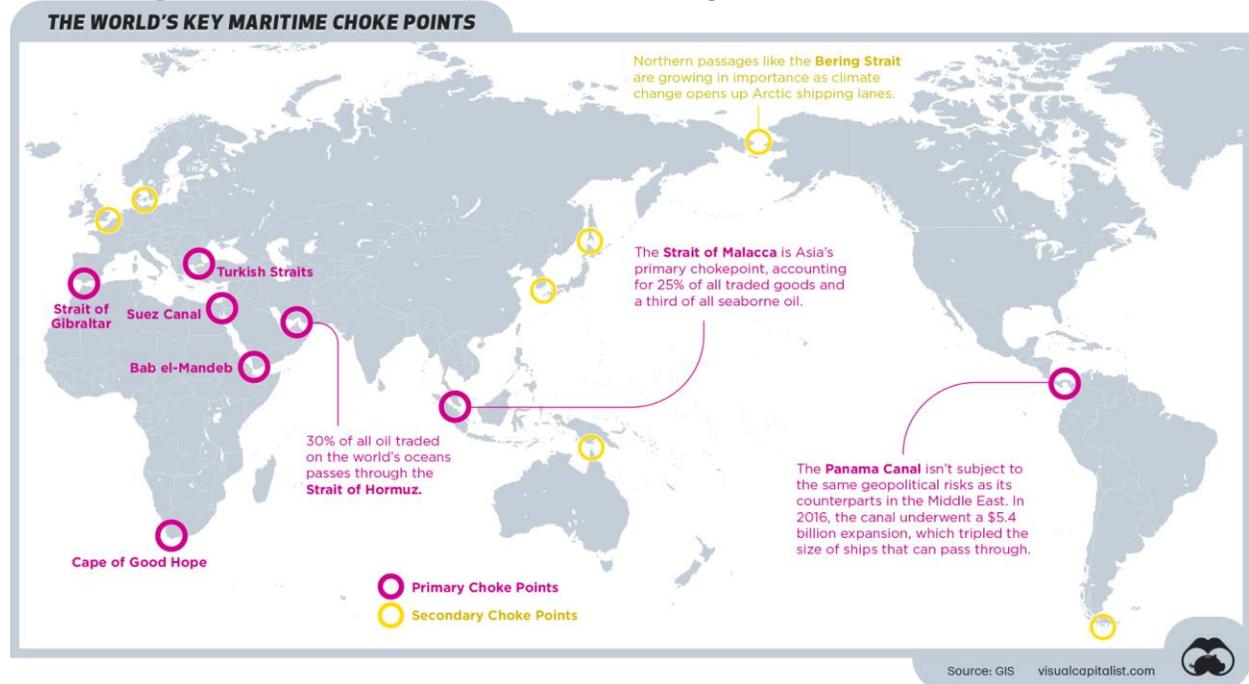
पनामा नहर

संदर्भ

हाल ही में अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पनामा नहर को पनामा को हस्तांतरित करने को एक "मूर्खतापूर्ण" निर्णय बताया तथा इसे अमेरिका को वापस करने की मांग की।

पनामा नहर के बारे में -

- यह 80 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है जो पनामा के इस्तमूस के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है।
- यह एक लॉक-प्रकार की नहर है जिसका स्वामित्व और प्रशासन पनामा के पास है।
- यह दुनिया के प्रमुख चोक पॉइंट्स में से एक है। यह दुनिया के 6% समुद्री व्यापार को संभालता है।



ट्रम्प पनामा से क्यों नाराज़ हैं?

- **उच्च पारगमन शुल्क:** पनामा नहर प्राधिकरण (ACP) ने अमेरिकी जहाजों के लिए पारगमन शुल्क बढ़ा दिया।
 - गैटुन और अल्हाजुएला झीलें, जो नहर के तालों को संचालित करने के लिए पानी की आपूर्ति करती हैं, में 2023 में भयंकर सूखे के कारण, नहर की शिपिंग क्षमता में 36% की कमी आई।
 - कम क्षमता की भरपाई के लिए, एसीपी ने शुल्क बढ़ा दिया, जिससे व्यापार के लिए नहर पर अत्यधिक निर्भर अमेरिकी जहाज प्रभावित हुए।
- **चीनी उपस्थिति में वृद्धि:** 2017 के बाद से, जब पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया, तब से नहर में चीनी निवेश में वृद्धि हुई है।

अमेरिका - पनामा संधि

- इसे टोरीजोस-कार्टर संधि के नाम से भी जाना जाता है, इस संधि पर 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा द्वारा पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को हस्तांतरित करने के लिए हस्ताक्षर किये गये थे।
- दिसंबर 1999 में इसे पनामा को हस्तांतरित कर दिया गया। पनामा ने परिवर्तन के बाद नहर के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ले ली।
- **स्थायी तटस्थता संधि:** नहर को तटस्थ घोषित किया गया और सभी देशों के जहाजों के लिए इसे खुला रखा गया। इसने अमेरिका को नहर की तटस्थता की रक्षा करने और सैन्य आपात स्थितियों में मार्ग को प्राथमिकता देने का अधिकार भी दिया।

स्रोत:

- [द हिन्दू - ट्रम्प ने पनामा संधि को 'मूर्खतापूर्ण' क्यों कहा है?](#)



संपादकीय सारांश

क्या मतदाता धोखाधड़ी से निपटने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाना चाहिए?

संदर्भ

29 दिसंबर, 2024 को आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक-दूसरे पर दिल्ली की मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप, जैसे जानबूझकर नाम हटाना और बूथ कैप्चरिंग।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के साथ छेड़छाड़ के दावे, जिनमें मतदान के बाद दुरुपयोग भी शामिल है।

आधार की भूमिका और विशेषताएं

- **विशिष्ट पहचान:** आधार प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है।
- **वास्तविक समय प्रमाणीकरण:** आधार ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रदान करता है।
- **सीमाएँ:** आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इसे वैध गैर-निवासियों को जारी किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर मतदान के अधिकार की स्थापना नहीं करता है।

राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP), 2015

- **लॉन्च किया गया:** भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा।
- **उद्देश्य:** पंजीकृत मतदाताओं के आधार नंबर के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) को जोड़कर त्रुटिरहित और प्रमाणीकृत मतदाता सूची तैयार करना।
- हालाँकि, NERPAP के कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से 11 अगस्त 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद, जिसने निजता और डेटा के दुरुपयोग की चिंताओं के कारण कार्यक्रम को रोक दिया था।

आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के लाभ

- **डुप्लिकेट मतदाता पहचान-पत्रों का उन्मूलन:** माइग्रेशन या पता परिवर्तन के कारण अक्सर डुप्लिकेट मतदाता पंजीकरण हो जाते हैं। लिंकिंग से ऐसे डुप्लिकेट की पहचान की जा सकती है और उन्हें समाप्त किया जा सकता है।
 - गोवा में बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण के साथ इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन आधार लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया।
- **प्रॉक्सी वोटिंग पर रोक:** आधार प्रमाणीकरण से मतदान के दौरान छद्म मतदान को रोका जा सकता है।
- **मतदाता सूची में पारदर्शिता:** यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही मतदाता पहचान पत्र हो।
 - रोल में त्रुटियों या जानबूझकर की गई हेराफेरी की पहचान करने में सहायता करता है।

आधार को मतदाता पहचान-पत्र से जोड़ने से जुड़ी चिंताएं

- **निजता और डेटा सुरक्षा:** आधार में संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा होता है, और इसे मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने से अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग की चिंता उत्पन्न हो सकती है।

- **बहिष्करण जोखिम:** तकनीकी त्रुटियाँ, आधार की उपलब्धता का अभाव, या बेमेल डेटा के कारण वास्तविक मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
- **नागरिकता का प्रमाण नहीं:** आधार को भारत में कानूनी रूप से रहने वाले गैर-नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है, जिससे यह मतदाता पात्रता के लिए एकमात्र सत्यापन के रूप में अनुपयुक्त हो जाता है।
- **दुरुपयोग की संभावना:** आधार को लिंक करने से अनजाने में राजनीतिक दलों को मतदाता विवरण तक पहुंच मिल सकती है, जिससे लक्षित अभियान या अवांछित संचार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **मानवीय एवं प्रणालीगत त्रुटियाँ:** आधार डेटाबेस में त्रुटियाँ (जैसे, गलत प्रविष्टियाँ) मतदाता सूची से जुड़ने पर विसंगतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **कानूनी स्पष्टता का अभाव:** चुनावी प्रक्रिया में आधार के उपयोग के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके और निजता कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी की भूमिका:** आधार डुप्लीकेशन जैसी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
- **मानवीय और संस्थागत अखंडता:** राजनीतिक और प्रशासनिक कदाचार को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- **ECI की जिम्मेदारी:** संदेह दूर करने और चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए सक्रिय संचार और कार्रवाई।

स्रोत:

- **द हिंदू: क्या मतदाता धोखाधड़ी से निपटने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाना चाहिए?**



दिल्ली चुनाव से पहले नकदी हस्तांतरण नीति

संदर्भ

दिल्ली चुनाव से पहले आप के नकदी हस्तांतरण वादों (दिल्ली महिला सम्मान योजना) पर विवाद ने इस बात पर बहस को जन्म दिया है कि क्या ऐसी योजनाएं वास्तविक कल्याणकारी पहल हैं या फिर अल्पकालिक लेन-देन की राजनीति से प्रेरित हैं।

नकद हस्तांतरण नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

पहलू	पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
राजकोषीय प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> कमजोर आबादी को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करता है। क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। 	<ul style="list-style-type: none"> इससे महत्वपूर्ण राजकोषीय बोझ पड़ता है, तथा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा जैसे दीर्घकालिक निवेशों से धन हट जाता है। इससे शिक्षा और स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के लिए अपर्याप्त वित्तपोषण हो सकता है।
निर्भरता	<ul style="list-style-type: none"> स्थिर आय के बिना परिवारों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> इससे निर्भरता की संस्कृति पैदा होने, रोजगार और उद्यमशीलता के प्रयासों को हतोत्साहित करने का जोखिम है। कार्य नैतिकता और कौशल विकास को कमजोर कर सकता है।
मुद्रास्फीति दबाव	<ul style="list-style-type: none"> मांग में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। 	<ul style="list-style-type: none"> इससे स्थानीय मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और नकदी हस्तांतरण की क्रय शक्ति कम हो सकती है।
सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना	<ul style="list-style-type: none"> गरीबी और बेरोजगारी जैसी तात्कालिक चुनौतियों से सीधे तौर पर निपटता है। हाशिए पर पड़े समूहों को लक्ष्य करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। 	<ul style="list-style-type: none"> यह अल्पकालिक राहत तो प्रदान करता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या रोजगार सृजन की कमी जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने में विफल रहता है। जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को अधिक सरल बना दिया जा सकता है, जिसके लिए गहन नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।
दुरुपयोग का खतरा	<ul style="list-style-type: none"> अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि प्राप्तकर्ता आमतौर पर पोषण और शिक्षा जैसी आवश्यक चीजों पर धन खर्च करते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> बिना शर्त हस्तांतरण का दुरुपयोग गैर-आवश्यक या हानिकारक गतिविधियों (जैसे, शराब, जुआ) पर किया जा सकता है। कार्यान्वयन या लाभार्थी पहचान में अकुशलता का जोखिम।
चुनावी और राजनीतिक प्रभाव	<ul style="list-style-type: none"> जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करना तथा चुनावी वादों को पूरा करना। 	<ul style="list-style-type: none"> इसे अक्सर चुनावों के करीब लाया जाता है, और वोट हासिल करने के उद्देश्य से लोकलुभावन उपाय के रूप में देखा जाता है।

	<ul style="list-style-type: none"> राजनीतिक वैधता और जवाबदेही को बढ़ाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की अपेक्षा अल्पकालिक राजनीतिक लाभ पर ध्यान केन्द्रित करें।
हिस्सेदारी	<ul style="list-style-type: none"> महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण करने में सहायता करता है, तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों के लिए समावेशी विकास का समर्थन करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> बिना शर्त स्थानान्तरण प्रभावी रूप से लक्षित नहीं हो पाता, जिससे अयोग्य व्यक्तियों को लाभ मिलता है। सार्वभौमिक योजनाओं में संसाधनों के इतना अधिक बिखराव होने का खतरा रहता है कि वे पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाते।
आर्थिक अवसर लागत	<ul style="list-style-type: none"> उपभोग को बढ़ावा देकर तत्काल आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। 	<ul style="list-style-type: none"> कौशल विकास जैसे उच्च दीर्घकालिक रिटर्न वाले वैकल्पिक निवेशों से संसाधनों को हटाना।
वहनीयता	<ul style="list-style-type: none"> कुशल कार्यान्वयन के लिए मौजूदा डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना (जैसे, डीबीटी)। बिचौलियों को दरकिनार करके पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है और लीकेज को न्यूनतम किया जाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> स्पष्ट निकास रणनीतियों या स्थायी राजस्व स्रोतों के बिना दीर्घकालिक स्थिरता के मुद्दे सामने आते हैं। यदि इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया तो सामाजिक-राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस: सहमत/असहमत

विस्तृत कवरेज

ध्रुवीकरण: इसके कारणों, विकास और प्रभाव पर गहन शोध

संदर्भ

ध्रुवीकरण की अवधारणा समकालीन अमेरिकी समाज और राजनीति की एक परिभाषित विशेषता बन गई है, विशेष रूप से 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की जीत और 2024 में उनके पुनः चुनाव के बाद।

ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है?

- इसका प्रयोग समाज को विरोधी समूहों में विभाजित करने (राजनीतिक ध्रुवीकरण) तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना (समूह ध्रुवीकरण) के लिए किया जाता है, जिसमें लोग चर्चा के बाद अधिक चरम रुख अपना लेते हैं।

ध्रुवीकरण के कारण क्या हैं?

- **पहचान-समूह राजनीति:** पहचान-आधारित संबद्धता पर बढ़ते जोर ने विभाजन को तीव्र कर दिया है।
 - **उदाहरण के लिए,** विभिन्न समूह विशिष्ट सांस्कृतिक या नस्लीय पहचान के इर्द-गिर्द एकजुट होते हैं, जिससे समूह के भीतर मजबूत निष्ठा पैदा होती है और बाहरी समूहों (जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर) के प्रति विरोध पैदा होता है।
- **धार्मिक और जातीय विविधता:** बढ़ती विविधता से सामाजिक विश्वास में कमी आ सकती है और सामाजिक संघर्ष बढ़ सकता है।
 - **उदाहरण के लिए,** भारत में, धार्मिक विविधता के कारण कभी-कभी विभिन्न जातीय समूहों के बीच सांप्रदायिक हिंसा और तनाव उत्पन्न होता है (जैसे मणिपुर में कुकी मैतेई संघर्ष)
- **आय असमानता:** बढ़ती आर्थिक असमानताएं निम्न आय वर्ग के लोगों में वंचितता की भावना को बढ़ावा दे सकती हैं।
 - **उदाहरण के लिए,** संयुक्त राज्य अमेरिका में, बढ़ती हुई धन असमानता को लोकलुभावन आंदोलनों के लिए बढ़ते समर्थन से जोड़ा गया है, जो अक्सर राजनीतिक विमर्श को ध्रुवीकृत कर देते हैं।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म:** सोशल मीडिया ऐसे प्रतिध्वनि कक्षों का निर्माण कर सकता है जो मौजूदा मान्यताओं को मजबूत करते हैं, जबकि उपयोगकर्ताओं को विरोधी दृष्टिकोणों से अलग कर देते हैं।
 - **उदाहरण के लिए,** फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को मुख्य रूप से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ने की अनुमति देते हैं, जिससे अधिक चरम राजनीतिक विचार सामने आ सकते हैं और भिन्न विचारों के संपर्क में कमी आ सकती है।
- **वैश्विक परिदृश्य:** एकीकृत करने वाले बाहरी खतरे की अनुपस्थिति ने आंतरिक विभाजन को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।
 - **उदाहरण के लिए,** अमेरिका सहित कई देशों में, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बजाय घरेलू राजनीतिक संघर्षों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

भारत में ध्रुवीकरण का विकास

स्वतंत्रता के बाद का युग (1947-1960)

- **विभाजन और सांप्रदायिक तनाव:** 1947 के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंदू-मुस्लिम हिंसा हुई, जिससे सांप्रदायिक अविश्वास के बीज बोये गये।

पहचान की राजनीति का उदय (1970-1990 का दशक)

- **जाति-आधारित लामबंदी:** ऐसे राजनीतिक दल उभरे जो हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते थे और उच्च जाति के प्रभुत्व को चुनौती देते थे।

- **राम जन्मभूमि आंदोलन:** राजनीतिक दलों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वकालत करके प्रमुखता हासिल की, जिससे हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण तेज हो गया।

गठबंधन युग और क्षेत्रवाद (1990-2000 का दशक)

- **खंडित जनादेश:** किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण गठबंधन सरकारें बनीं और क्षेत्रीय दलों को प्रभाव मिला, जो अक्सर स्थानीय पहचान को बढ़ावा देते थे।
- **आर्थिक उदारीकरण:** 1991 में शुरू किए गए सुधारों से आर्थिक असमानताएं पैदा हुईं, जिससे वर्ग-आधारित ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला।

हिंदू राष्ट्रवाद का उदय (2010-वर्तमान)

- **नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोध:** सीएए के 2019 अधिनियमन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, आलोचकों ने आरोप लगाया कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है, जिससे सांप्रदायिक विभाजन गहराता है।
- **सोशल मीडिया का प्रभाव:** राजनीतिक दलों ने विचारधाराओं के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, कभी-कभी गलत सूचना के माध्यम से ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया।

हालिया घटनाक्रम (2020)

- **धार्मिक हिंसा:** सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण धार्मिक ध्रुवीकरण में वृद्धि है।
- **प्रवासी गतिशीलता:** भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण ने विदेशों में भारतीय समुदायों को प्रभावित किया है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसके कारण प्रवासी समुदाय के भीतर विभाजन पैदा हो गया है।

ध्रुवीकरण के प्रभाव

- **लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण:** तीव्र ध्रुवीकरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है, जिससे विधायी गतिरोध और नीति कार्यान्वयन में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी कांग्रेस को पक्षपातपूर्ण विभाजन के कारण कानून पारित करने में बड़ी हुई कठिनाई का सामना करना पड़ा है।
- **सामाजिक विखंडन:** ध्रुवीकरण सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है, नागरिकों के बीच और जनता और संस्थाओं के बीच विश्वास को खत्म करता है। यह विखंडन विरोधी समूहों के अमानवीकरण की ओर ले जा सकता है, जिससे राजनीतिक हिंसा का खतरा बढ़ जाता है।
- **विधायी शिथिलता:** पक्षपातपूर्ण राजनीति विधायी प्रक्रिया को धीमा कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कम कानून पारित होंगे और जब कानून पारित होगा तो संभवतः अधिक चरम नीतियों को लागू किया जाएगा।
- **आर्थिक और सामाजिक कल्याण में गिरावट:** ध्रुवीकरण उपभोक्ता कल्याण को नुकसान पहुंचा सकता है और व्यक्तियों के दैनिक जीवन में चुनौतियां पैदा कर सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण प्रभावित हो सकता है।

आगे की राह: ध्रुवीकरण को कम करने की रणनीतियाँ

- **समावेशी संवाद को बढ़ावा देना:** विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने वाली खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने से विभाजन को पाटने में मदद मिल सकती है। नागरिक सभाओं जैसी पहलों ने समझ को बढ़ावा देने और सहयोगात्मक समाधान उत्पन्न करने में वादा दिखाया है।
- **चुनावी सुधार:** ओपन प्राइमरी या रैंक-चॉइस वोटिंग जैसे बदलावों को लागू करने से उदारवाद को बढ़ावा मिल सकता है और पक्षपातपूर्ण अतिवाद को कम किया जा सकता है। उदारवादी उम्मीदवारों के अभियानों को सब्सिडी देने से अधिक मध्यमार्गी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिल सकता है।
- **मीडिया साक्षरता और जिम्मेदार उपभोग:** गलत सूचना की पहचान करने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने से विभाजनकारी सामग्री के प्रसार को कम किया जा सकता है। विविध समाचार स्रोतों के उपभोग को प्रोत्साहित करने से भी प्रतिध्वनि कक्षों को कम किया जा सकता है।
- **नागरिक शिक्षा को मजबूत करना:** लोकतंत्र के सिद्धांतों, समझौते के महत्व और प्रारंभिक उम्र से ही विविध दृष्टिकोणों के मूल्य को पढ़ाने से अधिक सहिष्णु समाज की नींव रखी जा सकती है।

- **अंतर-दलीय सहयोग को प्रोत्साहित करना:** द्विदलीय पहल को सुविधाजनक बनाना और सफल अंतर-दलीय प्रयासों को उजागर करना सहयोग के लाभों को प्रदर्शित कर सकता है और प्रतिकूल धारणाओं को कम कर सकता है।
- **अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना:** आर्थिक असमानताओं और सामाजिक अन्यायों से निपटना, जो अक्सर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं, एक अधिक समतामूलक समाज की ओर ले जा सकता है, तथा चरमपंथी पदों के आकर्षण को कम कर सकता है।

स्रोत:

- [द हिन्दू: विश्व के और अधिक 'ध्रुवीकृत' होने पर विचार](#)
- [ट्रेसिबिलिटी से परे](#)
- [एलियांज](#)

